शताब्दी में एक बार संकट आने की स्थिति में दृढ़ता

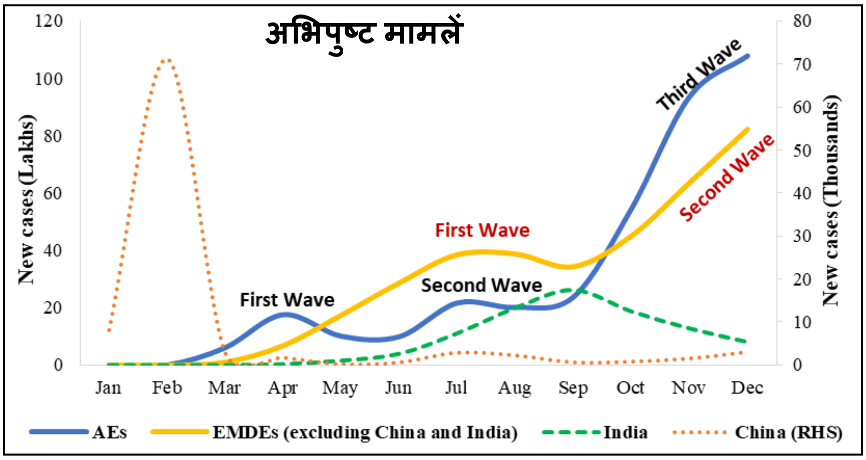

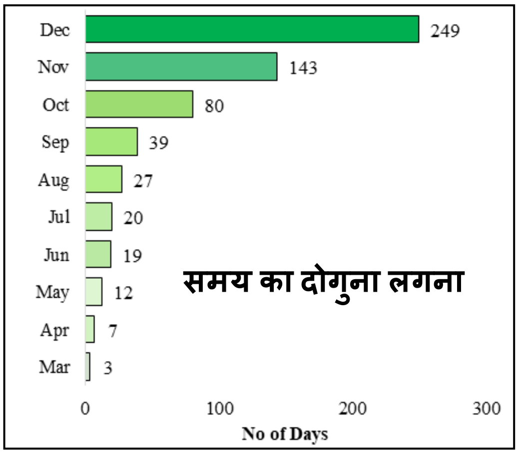

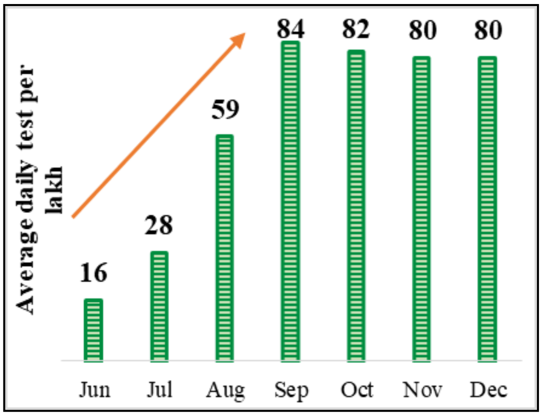

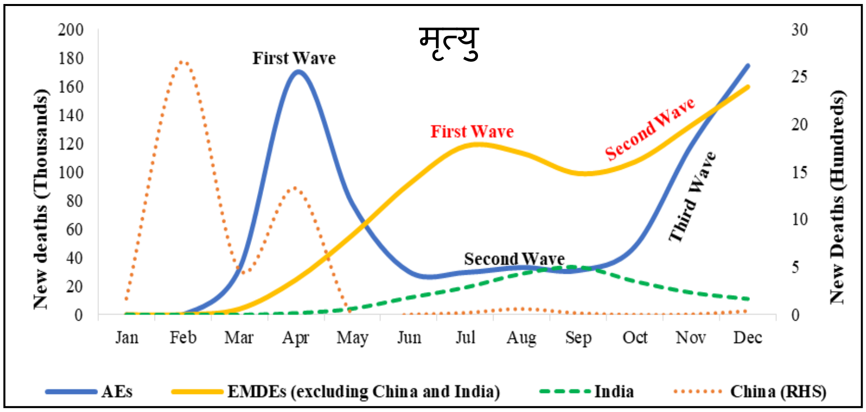

हम हैं रिकवरी की ओर अग्रसर

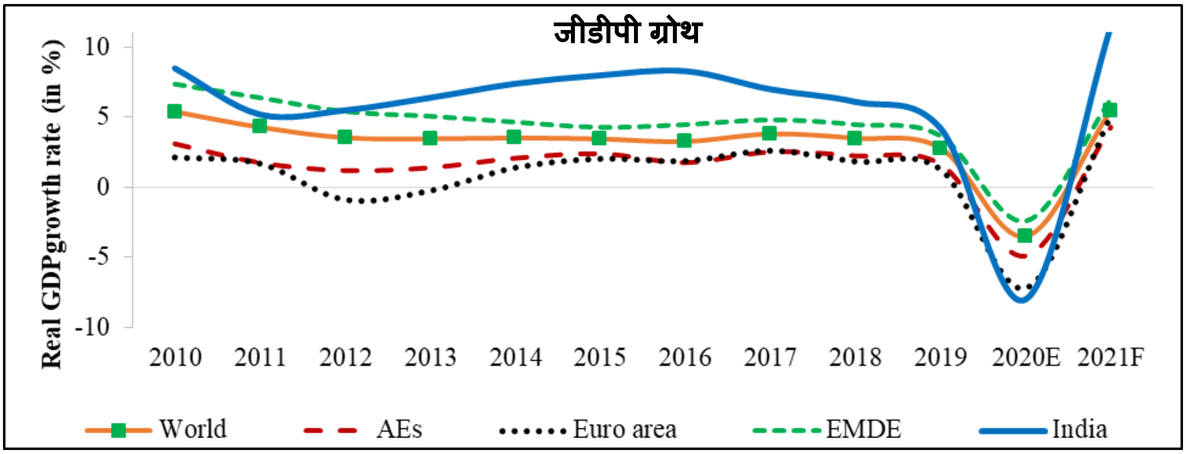

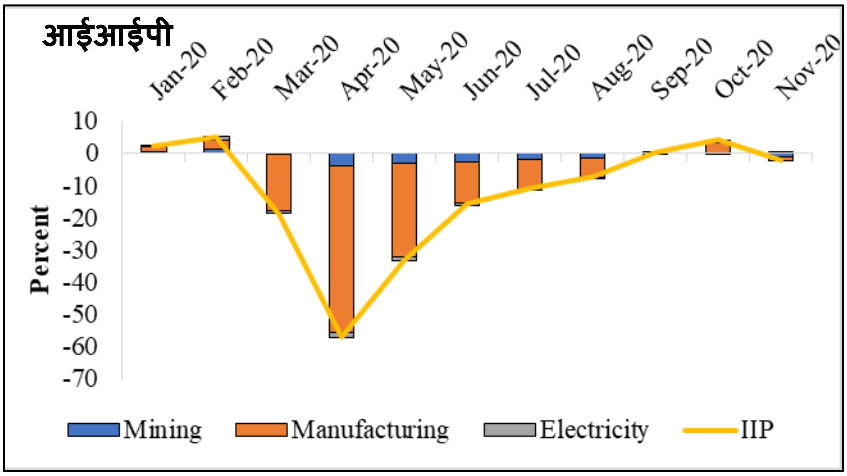

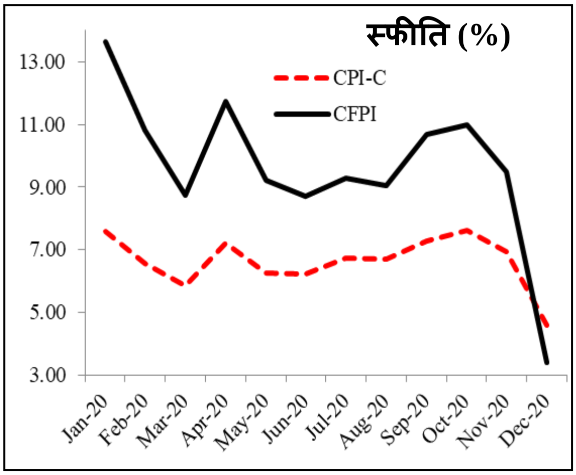

आत्म निर्भर भारत अभियान

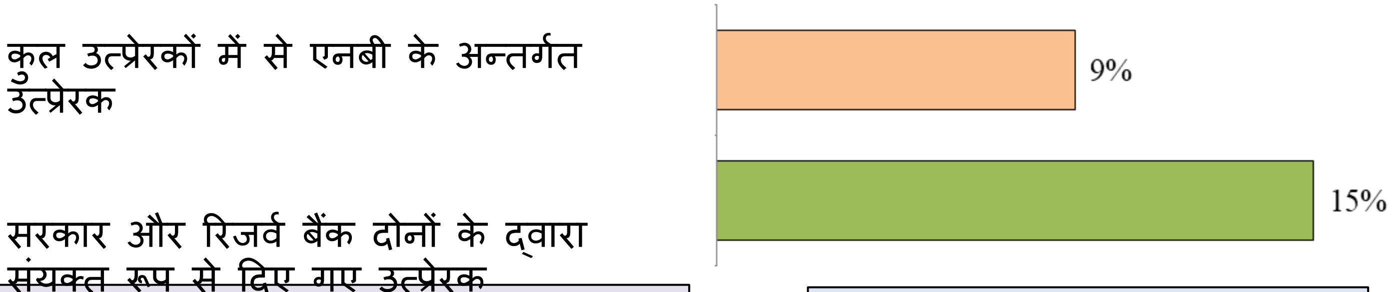

सरकारी सुधार

- राज्य सरकारों की उधार लेने की सीमा को बढ़ाना
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण

ऊर्जा

- डिस्काम को नकदी सहायता
- विनियामक परिसम्पतियों को हटाना
- वाणिज्यिक कोयला खनन
- क्रास - सब्सिडी

एमएसएमई और उद्योग

- कारोबार के लिए साम्पाश्रिवक ब्याज मुक्त ऋण
- एमएसएमई के फण्ड की स्थापना की जाएगी
- पीएम गरीब कल्याण योजना
- एमएसएमई को अधीनस्थ ऋण
- 200 करोड़ रूपये तक की वैश्विक निविद्धाओं को बन्द करना
- एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन

सामाजिक क्षेत्र

- नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लू प्रिन्ट
- मनरेगा के लिए अतिरिक्त आवंटन
- प्रौद्योगिकी प्रेरित शिक्षा पीएम ई-विद्या
- नेशनल फाउण्डेशनल लिटरेसी एण्ड न्यूमरेसी मिशन

प्रवासी श्रमिक

- ✓ एक राष्ट्र एक कार्ड
- ✓ प्रवासियों को खाद्यान्नों की मुफ्त आपूर्ति

कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र

- किसानों को कन्सेसनल क्रेडिट बूस्ट
- कृषि अवसंरचना कोष
- किसानों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी
- पशुपालन अवसंरचना विकास
- आवश्यक जिंस अधिनियम में संशोधन
- कृषि विपणन सुधार

स्वास्थ्य सम्बन्धी समग्र दृष्टिकोण

निवारक

दृष्टिकोण

निदानात्मक

कल्याण

पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को एक में मिलाकर मिशन पोषण 2.0 को शुरु किया जाएगा

पीएम आत्म निर्भर स्वस्थ भारत योजना

- छः वर्षों में परिव्यय 64180 करोड़ रुपए
- स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों को सहायता

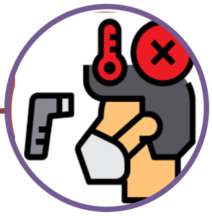

- एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालओं की स्थापना
- क्रिटिकल केयर हास्पिटल ब्लाक्स की स्थापना

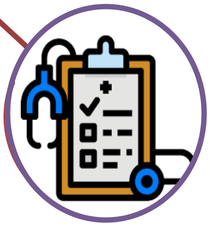

- एनसीडीसी को सुदृढ़ करना
- एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्ताव किया जाना

- न्यमोकोक्कल वैक्सीन को देशभर में लगाया जाना
- 2021-22 में कोविड-19 के लिए ₹35000 करोड़ रुपए

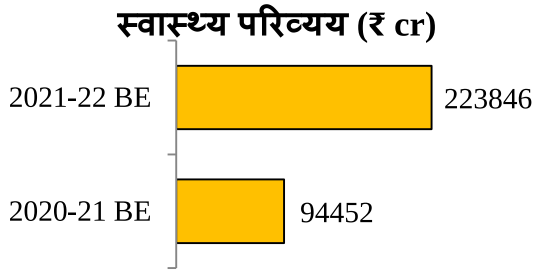

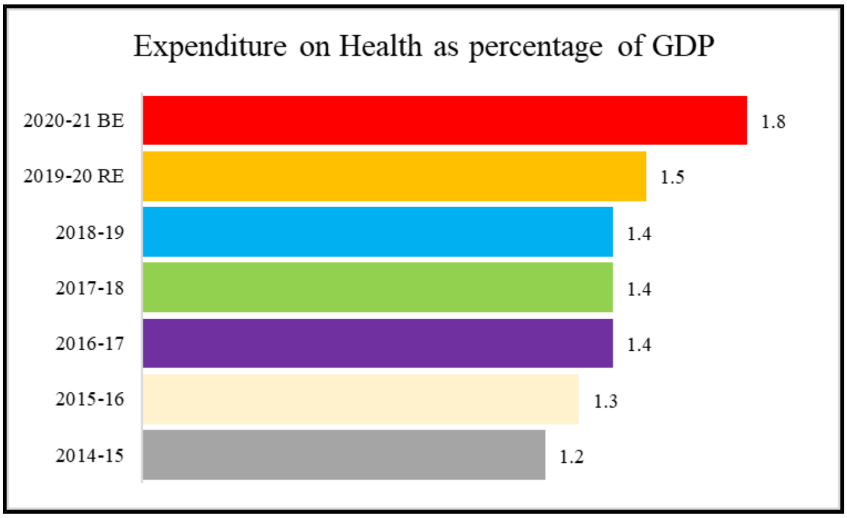

नेशनल कमीशन फार एलाइड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स बिल को पेश किया जाना

उद्योग

वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर अगले 5 वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपये की निर्धारित राशि से सभी 13 क्षेत्रों में मैन्यूफैक्चरिंग ग्लोबल चैम्पियन्स को पैदा करने के लिए पीएमआई को शुरू किया जाना

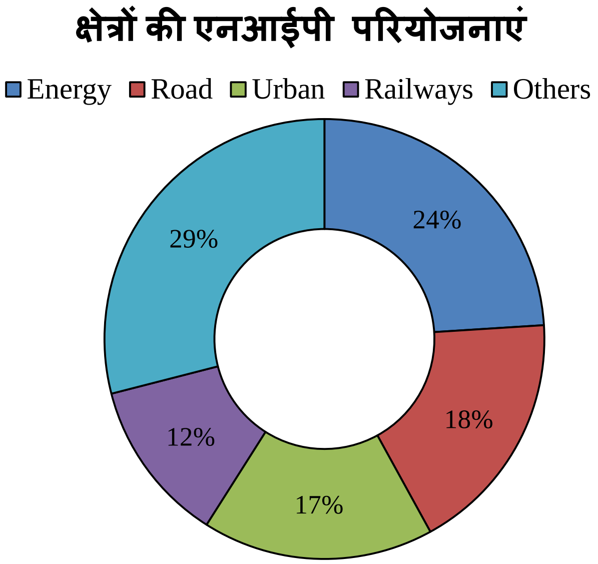

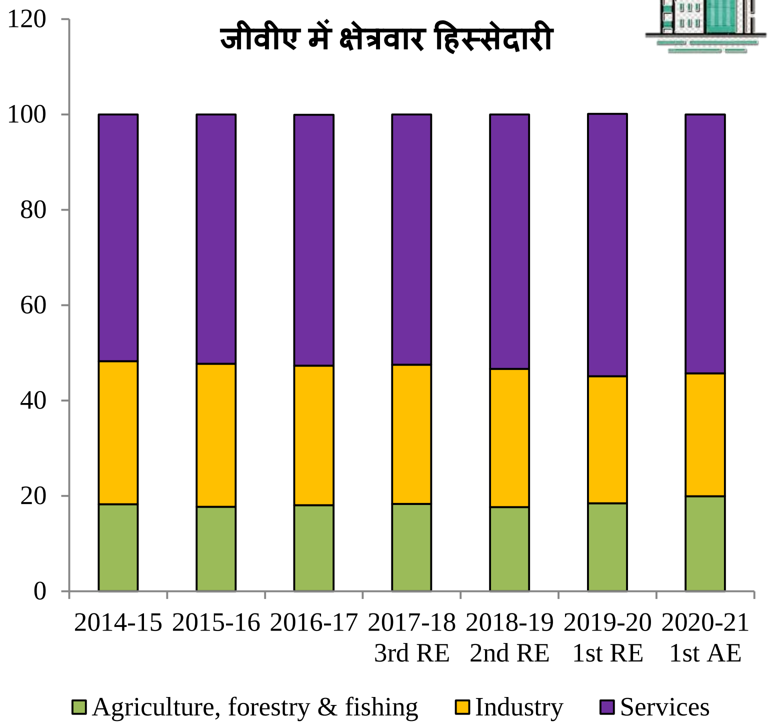

एनआईपी प्रोजेक्ट पाइप लाइन का 7400 परियोजनाओं तक विस्तार

कपड़ा क्षेत्र में ग्लोबल चैम्पियन्स के लिए विश्वस्तरी अवसंरचनाओं के सृजन के लिए मित्र स्कीम, जिससे 3 वर्षों 7 टेक्सटाइल पार्क्स तैयार किये जायेंगे

अवसंरचना

सड़क निर्माण प्रतिदिन कि. मी.

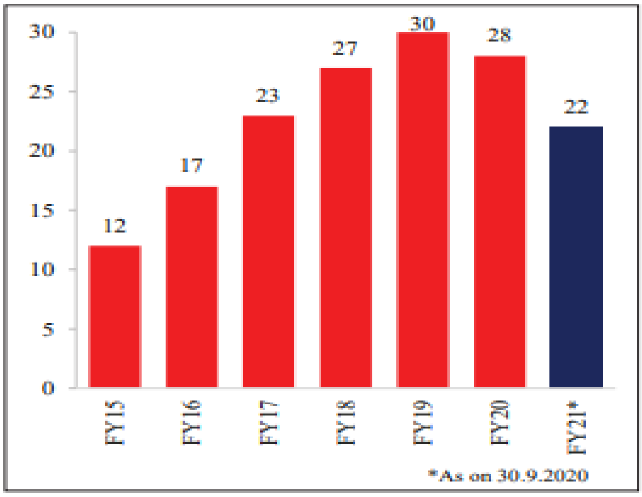

राष्ट्रीय रेल योजना

- 2030 तक पर्याप्त रेल अवसंरचना के विकास का उद्देश्य जिससे 2050 तक की प्रक्षेपित ट्रैफिक की जरूरतों की पूरा किया जा सकेगा
- इसका लक्ष्य माल भाड़े में रेल के माडल शेयर को 27 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 45 प्रतिशत तक करना है।

- 2023 तक ब्राड गेज रूट्स का 100% विद्युतीकरण
- स्वदेश में विकसित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली का शुभारंभ किया जाना

स्थापित संयन्त्र क्षमता (जीडब्लयू)

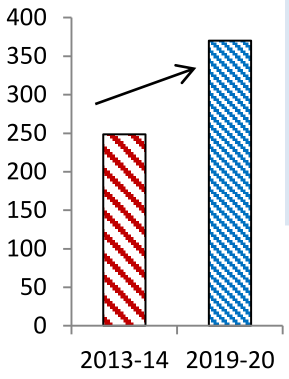

- ✓ 6 वर्षों में स्थापित क्षमता में 139 जीडब्ल्यू की बढ़ोतरी की गई जिससे 2.8 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को बिजली पहुंचायी गयी और 1.41 लाख सर्किट कि. मी. की अतिरिक्त ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई गई
- ✓ अगले पांच वर्ष में 3,05,984 करोड़ रूपए के परिव्यय से पुनसंरचित सुधार आधारित लिंक्ड विद्युत सेक्टर स्कीम लांच की जाएगी
- ✓ हाईड्रोजन ऊर्जा मिशन लांच किया जाएगा

पत्तन, नौपरिवहन और जल मार्ग

- बड़े पत्तनों की प्रचालन सेवाओं के प्रबन्धन के लिए पीपीपी मोड का उपयोग किया जाएगा
- मर्चेण्ट शिप्स को शुरू करने को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी सहायता
- रिसाइक्लिंग आफ शिप्स एक्ट, 2019 तैयार कर लिया गया है 2024 तक रिसाइक्लिंग क्षमता को दो गुना कर देना है

निष्पादन सूचक रैंक

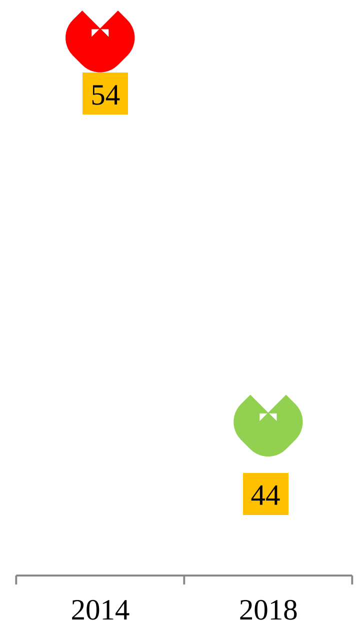

पीएनजी

- उज्जवला स्कीम में 1 करोड़ और लाभार्थियों को कवर करना
- 100 और जिलों को सिटी गैस वितरण नेटवर्क के अंतर्गत लाना
- स्वतंत्र गैस परिवहन प्रणाली आपरेटर स्थापित किया जाना है

अवसंरचना वित्तपोषण

- डीएफआई की स्थापना के लिए बिल पेश किया जाएगा
- नेशनल मानेटाइजेशन पाइपलाइन आफ ब्राउन फील्ड अवसंरचना आस्ति

शहरी

जल जीवन मिशन (शहरी) , सभी यूएलबी में जल की एक समान आपूर्ति के लिए

शहरी स्वच्छ भारत मिशन जिसके लिए अगले पांच वर्षों में ₹1,41,678 रूपए का परिव्यय रखा गया है

42 शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए ₹2,217

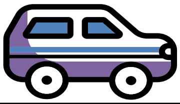

स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति

पब्लिक बस ट्रासंपोर्ट को बढ़ाने के लिए अभिनव परक पीपीपी मोडल

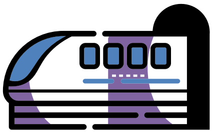

टीयर 2 के और टीयर 1 के परिधीय शहरों के लिए मेट्रो लाईट और मेट्रो नियो

वित्तीय सुधार

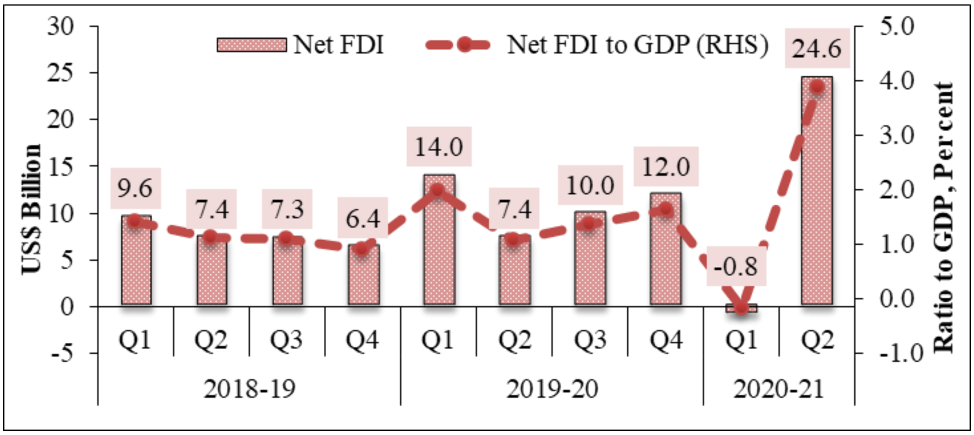

- ❖ 2022 तक रेशनालाईज सिंगल सिक्युरिटी मार्केट कोड
- ❖ जीआईएफटी आईएफएससी में विश्व स्तरीय फिनटेक हब
- ❖ कारपोरेट बांड मार्केट के लिए स्थायी संस्थागत ढांचा
- ❖ कमोडोटी मार्केट इको सिस्टम के विकास के लिए सेबी को विनियामक बनाना और डब्लयू डीआरए को और अधिक भूमिका सौंपना
- ❖ सभी वित्तीय उत्पादों में अधिकार के रूप में इन्वेस्टर चार्टर
- ❖ बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन जिससे कि रक्षोपाय के साथ एफडीआई की सीमा बढ़ाई जा सके
- ❖ पीएसबी की दबाव पूर्ण परिसंपति समस्या के समाधान के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लि. और एसेट मैनेजमेंट कम्पनी

समग्र विकास

कृषि

- ❑ सभी राज्य/सभी संघ राज्य क्षेत्रों को स्वामित्व स्कीम के दायरे में लाना
- ❑ शीघ्र खराब होने वाले 22 उत्पादों को शामिल करने के लिए आपरेशन ग्रीन स्कीम का विस्तार
- ❑ 1000 और मंडियों को ई-नाम से जोड़ना

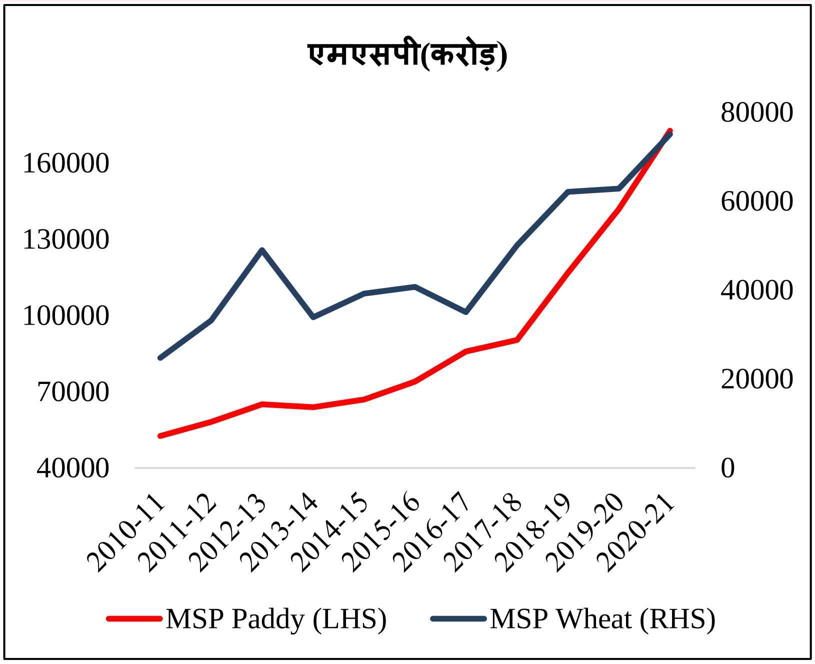

मत्स्य पालन

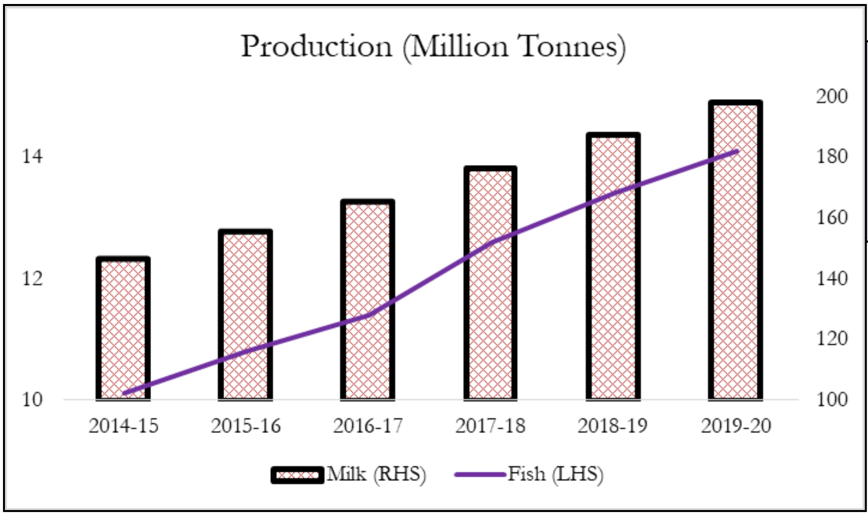

- ○ आधुनिक मत्स्य बंदरगाहों और मत्स्य तटाव केन्द्रों का विकास
- ○ तमिलनाडु में मल्टी परपज सीबीड पार्क की स्थापना

प्रवासी मजदूर और श्रमिक

- ➢ एक राष्ट्र एक कार्ड स्कीम को 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा है
- ➢ गीग, बिल्डिंग निर्माण कार्य में मजदूरों के लिए एक पोर्टल चालू करना
- ➢ गीग और प्लेटफार्म के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराना

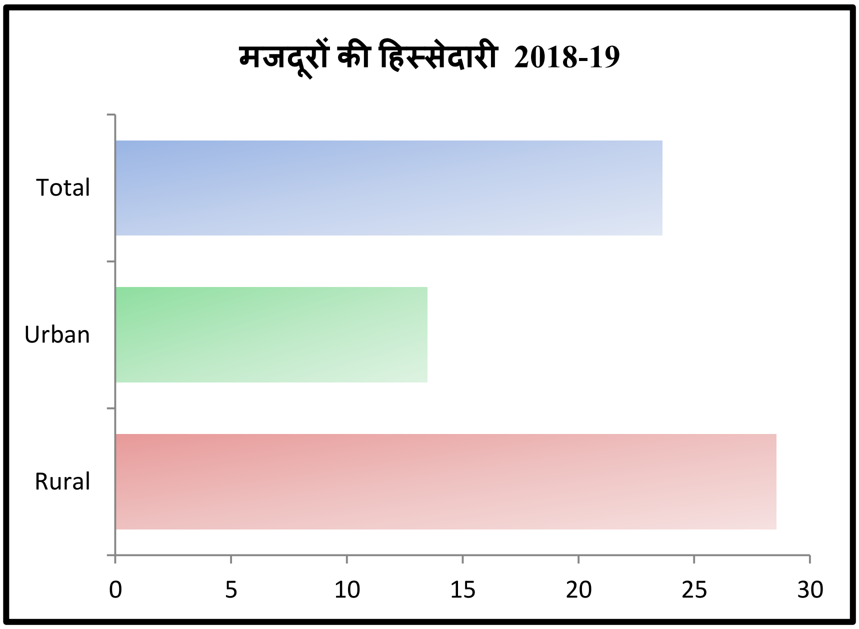

मानव पूंजी

शिक्षा

- अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए रिवाम्प्ड पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम
- 100 नये सैनिक स्कूल
- जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल

कौशल

- इन्जीनियरिंग के स्नातकों और डिप्लोमा होल्डरों के लिए नेशनल एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का पुनः सुयोजन
- कौशल विकास और इसकी मान्यता के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात और जापान के साथ भागीदारी

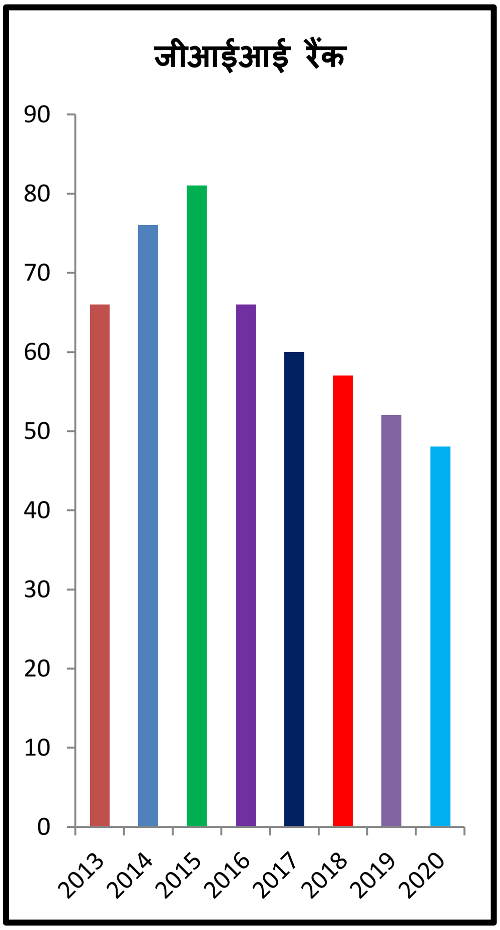

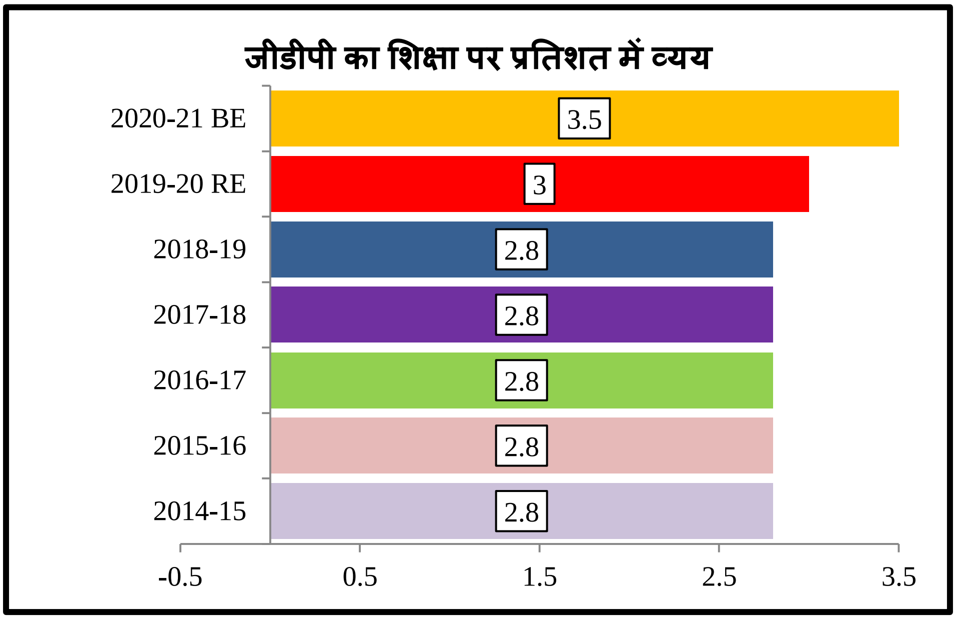

अनुसंधान और विकास

- ✓ अगले 5 वर्षों में ₹50,000 करोड़ के परिव्यय से नेशनल रिसर्च फाउडेशन
- ✓ इन्टरनेट तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन
- ✓ समुद्री अन्वेषण और जैव विविधता संरक्षण के लिए डीप ओसियन मिशन

राजकोषीय स्थिति

1

- 2021-22 में राज्यों को जीएसडीपी के 4 प्रतिशत तक निवल ऋण लेने की अधिकतम सीमा की स्वीकृति
- कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए जीएसडीपी के 0.5% तक की अधिकतम सीमा तक अतिरिक्त कर्ज ले सकना

2

खाद्य सब्सिडी के लिए भारतीय खाद्य निगम को एनएसएसएफ ऋण , जिसके स्थान पर बजट प्रावधान किये जायेंगे

3

2021-22 में 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुमान के रूप में ₹1,18,452 करोड़

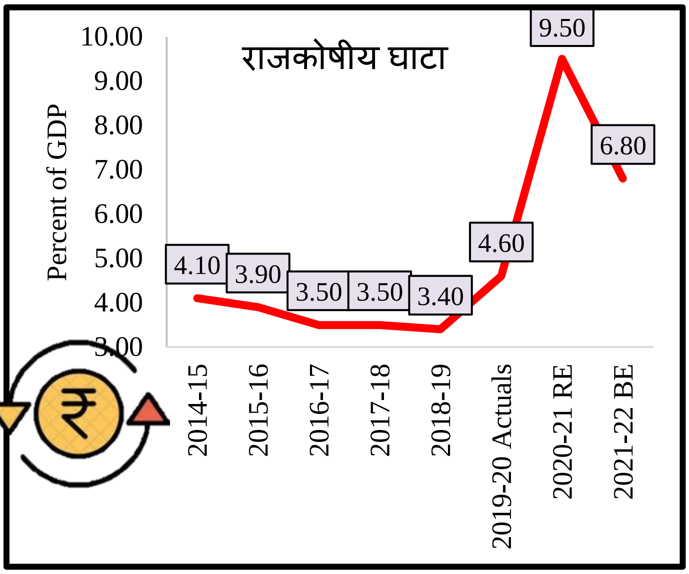

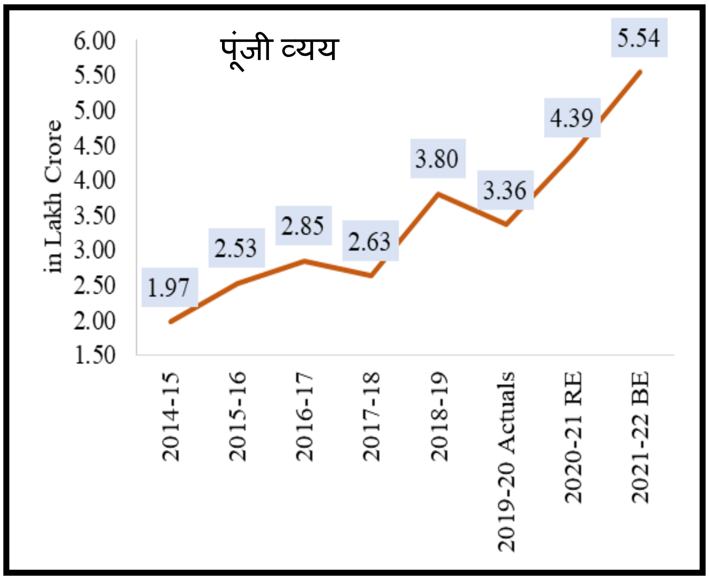

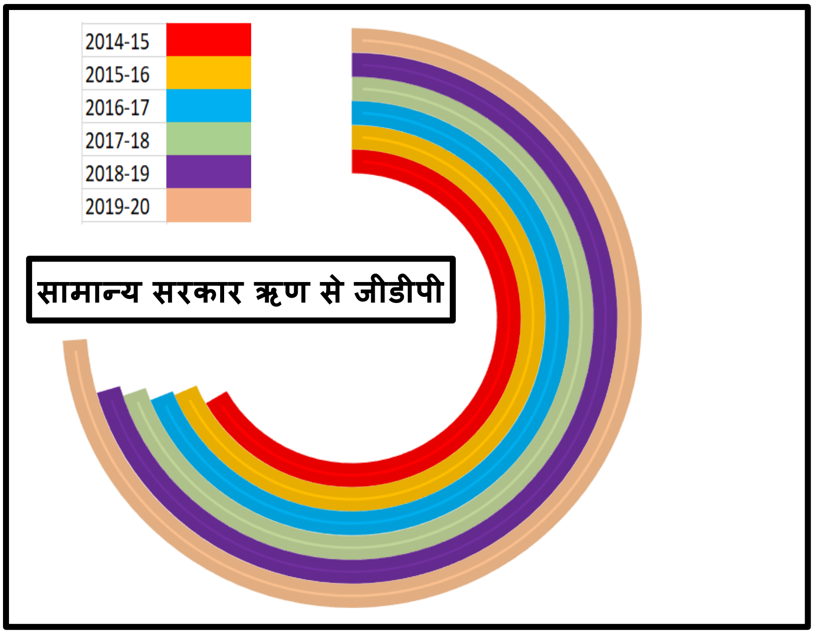

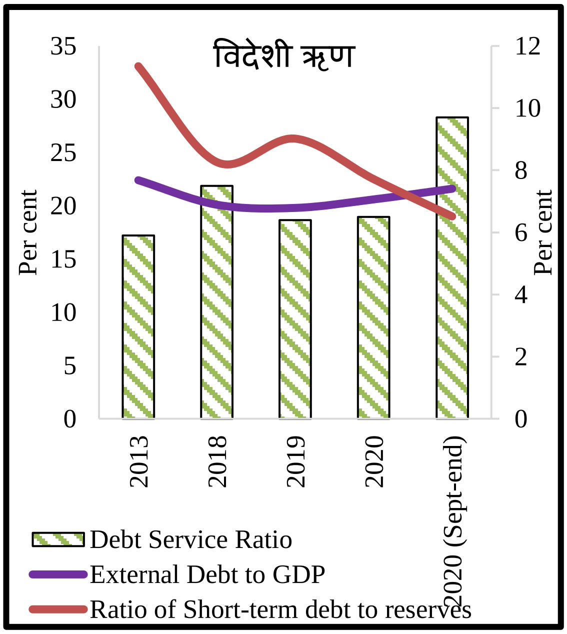

कर प्रस्ताव

टैक्स रिटर्न दायर करने वाले (करोड़)

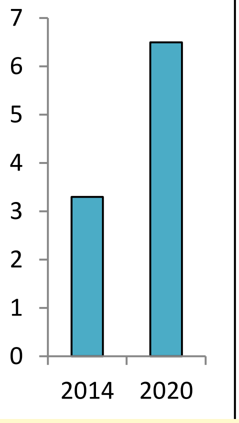

इन वरिष्ठ नागरिकों (75 वर्ष और इससे अधिक उम्र के) को आयकर का रिटर्न भरने से छूट देना जिनकी आय का स्रोत केवल पेन्शन और उस पर मिलने वाला ब्याज है

आयकर के आकलन को फिर से खुलवाने की समय सीमा को कम करना

छोटे मोटे करदाताओं के लिए एक विवाद निपटान समिति का गठन

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण को फेसलेस बनाया जाना है

करदाता जिन्होंने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजनाओं को स्वीकार किया है

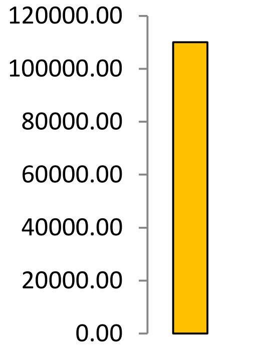

ऐसे व्यक्तियों के लिए कर के लेखा-परीक्षा की सीमा को बढ़ाना जो अपना 95 प्रतिशत लेन-देन डिजिटल रूप से करते हैं

आरईआईटी/इन्वी आईटी को भुगतान किये जाने वाले लाभांश को टीडीएस से छूट देना

सस्ते मकानों की खरीद के लिए 31 मार्च 2022 तक लिए जाने वाले ऋण पर 1.5 लाख रूपये की अतिरिक्त कटौती सुलभ होगी

पहले से रिटर्न फाइल करने पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों , लाभांश आय आदि से पूंजीगत आय को कवर करेगा

स्टार्ट अप के लिए टैक्स होलिडे का दावा करने की पात्रता को एक और वर्ष बढ़ाया जाना प्रस्तावित है

आयकर

जीएसटी संग्रहण

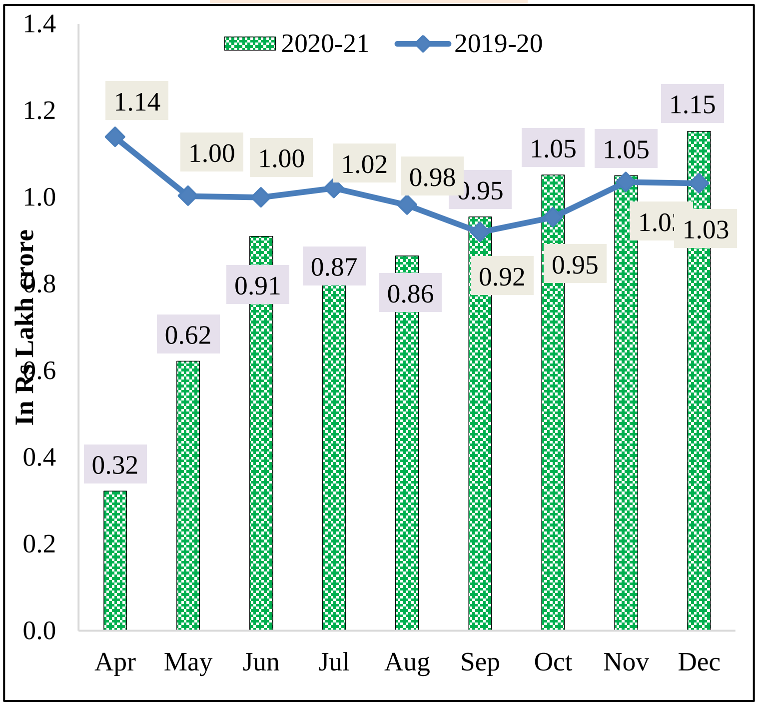

- ❖ पुरानी छूटों को समाप्त करके सीमाशुल्क की संरचना को युक्तिसंगत बनाना
- ❖ आयरन और स्टील की कीमतों में हाल ही में तेजी से ही वृद्धि के कारण आहत एमएसएमई को सहायता और मेटल रिसाईक्लर्स को राहत
- ❖ मानव निर्मित वस्त्रों के कच्चे माल इन्पुट पर लगने वाले शुल्क को युक्ति संगत बनाना
- ❖ सोने और चांदी पर लगने वाले सीमाशुल्क को युक्तिसंगत बनाना
- ❖ घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सोलर इन्वर्टर और लालटेन पर लगने वाले शुल्क में वृद्धि करना
- ❖ कम संख्या में मदों पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर

रूपये का आगमन

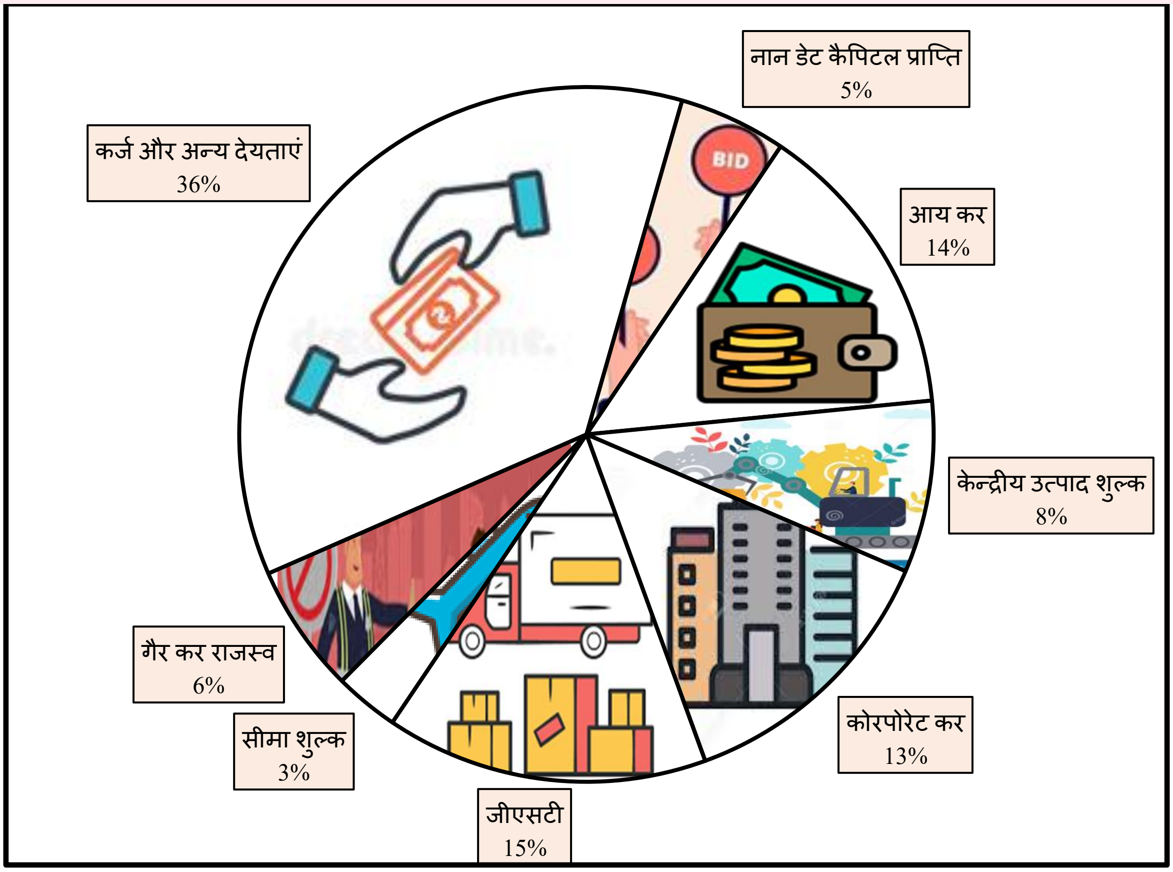

रूपये का गमन

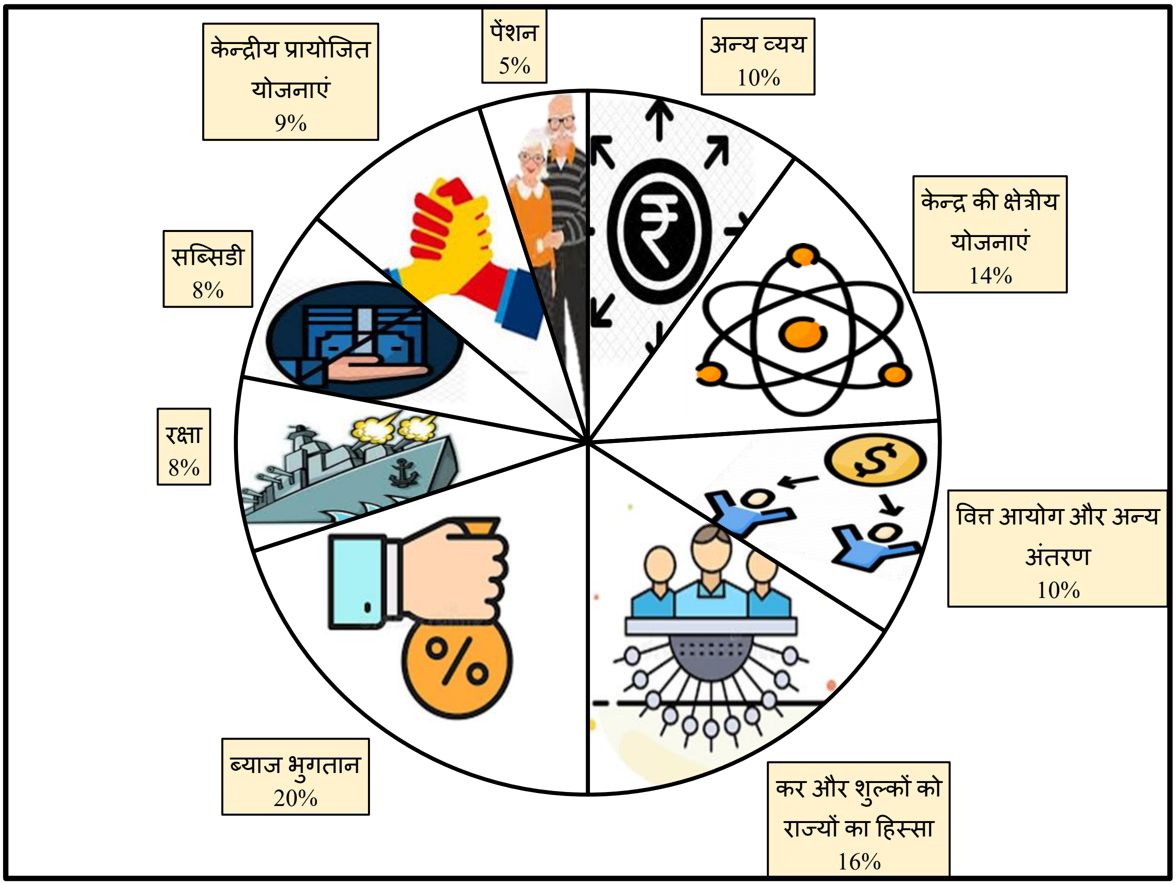

प्रमुख योजनाओं का आवंटन

मनरेगा (करोड़)

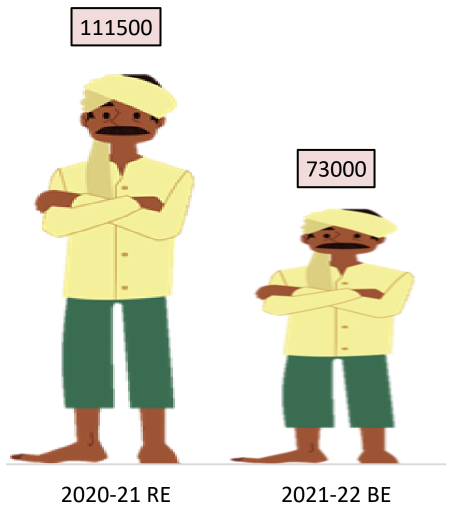

पीएम किसान (करोड़)

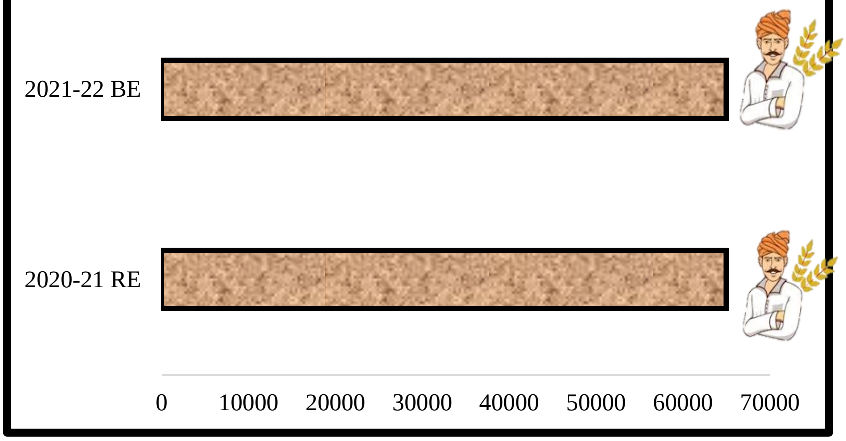

राष्ट्रीय शिक्षा मिशन(करोड़)

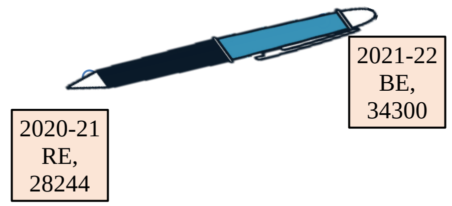

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (करोड़)

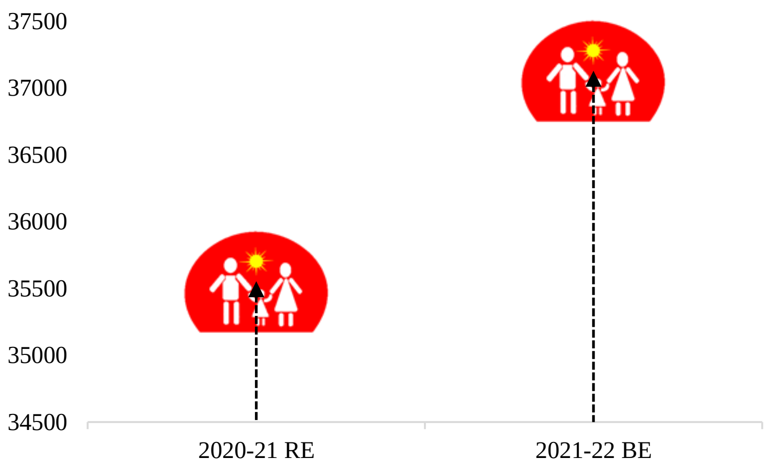

जल जीवन मिशन (करोड़)

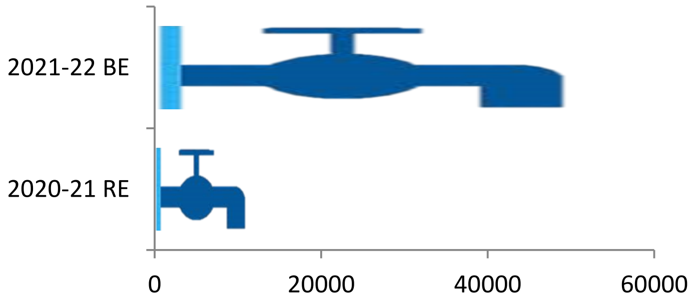

अमृत और स्मार्ट शहर (करोड़)

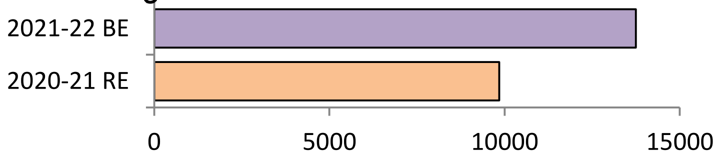

मेट्रो प्रोजेक्ट (करोड़)

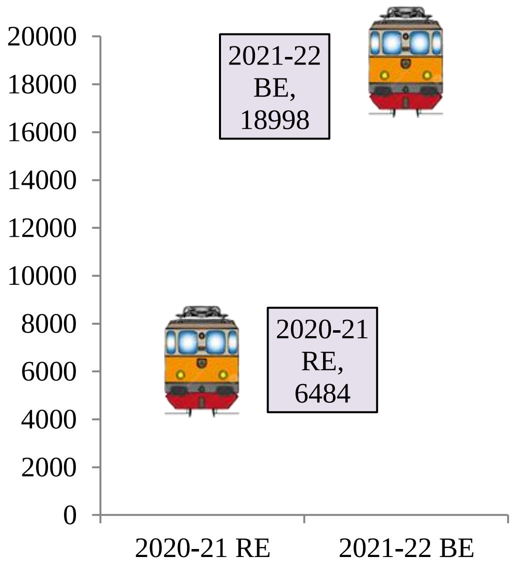

बजट पर एक नजर

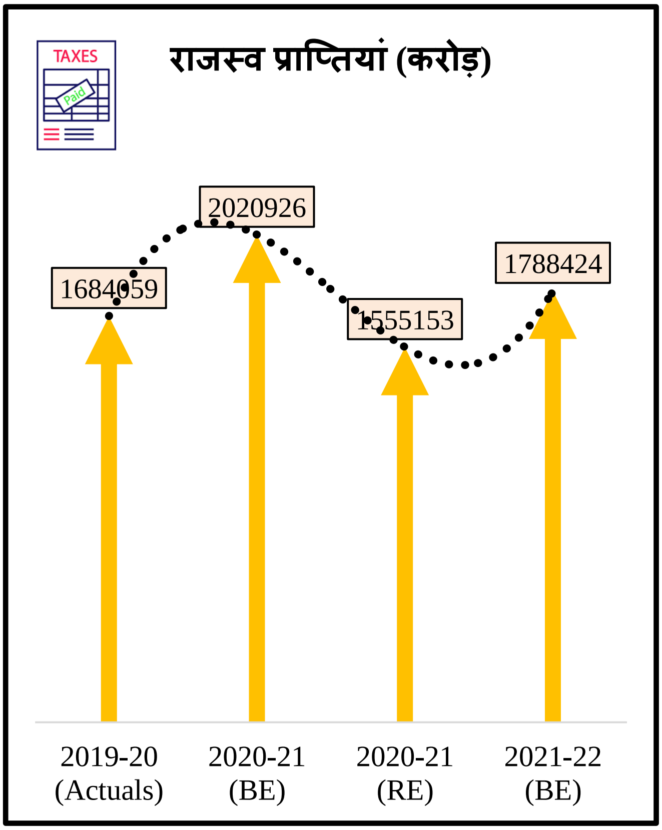
TAXES
Paid
राजस्व प्राप्तियां (करोड़)
1684059
2020926
1555153
1788424
2019-20 (Actuals)
2020-21 (BE)
2020-21 (RE)
2021-22 (BE)

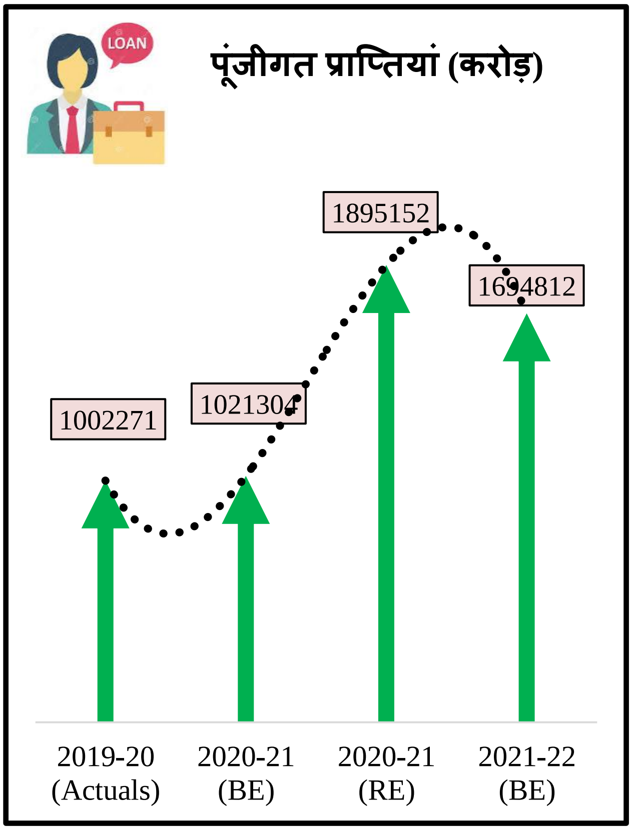
LOAN
पूंजीगत प्राप्तियां (करोड़)
1002271
1021304
1895152
1694812
2019-20 (Actuals)
2020-21 (BE)
2020-21 (RE)
2021-22 (BE)

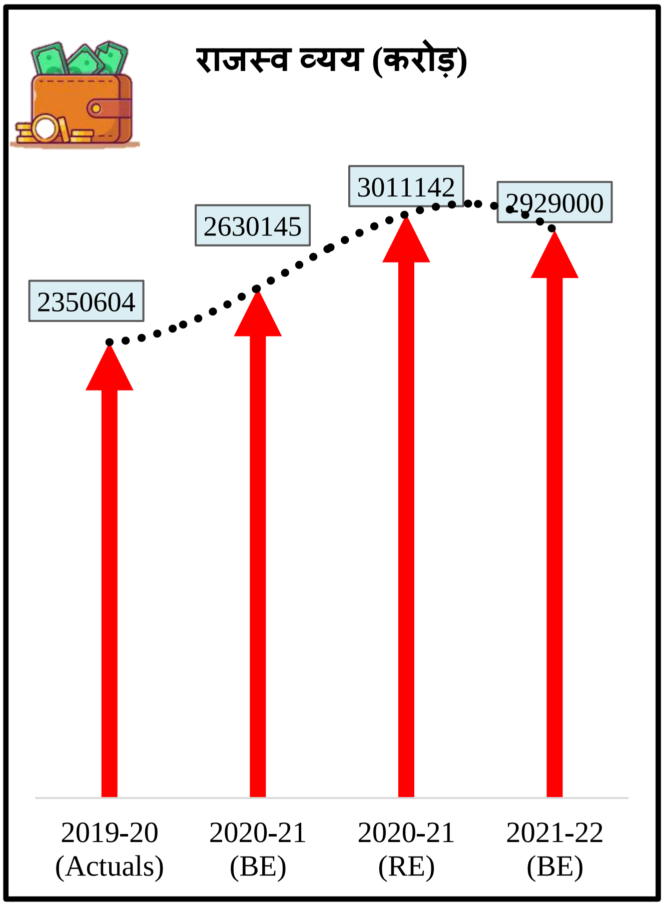
राजस्व व्यय (करोड़)
2350604
2630145
3011142
2929000
2019-20 (Actuals)
2020-21 (BE)
2020-21 (RE)
2021-22 (BE)

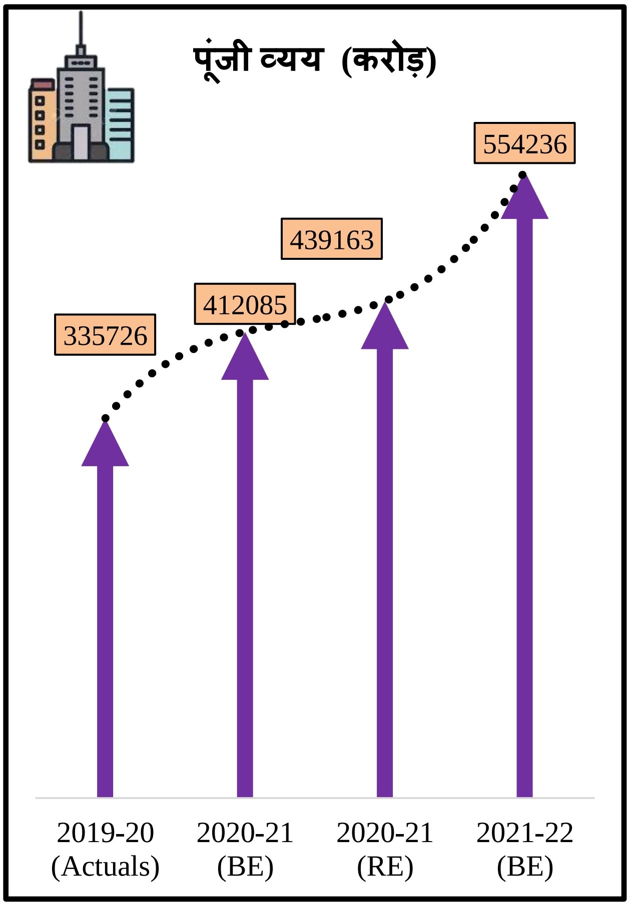
पूंजी व्यय (करोड़)
335726
412085
439163
554236
2019-20 (Actuals)
2020-21 (BE)
2020-21 (RE)
2021-22 (BE)

प्रमुख आवंटन

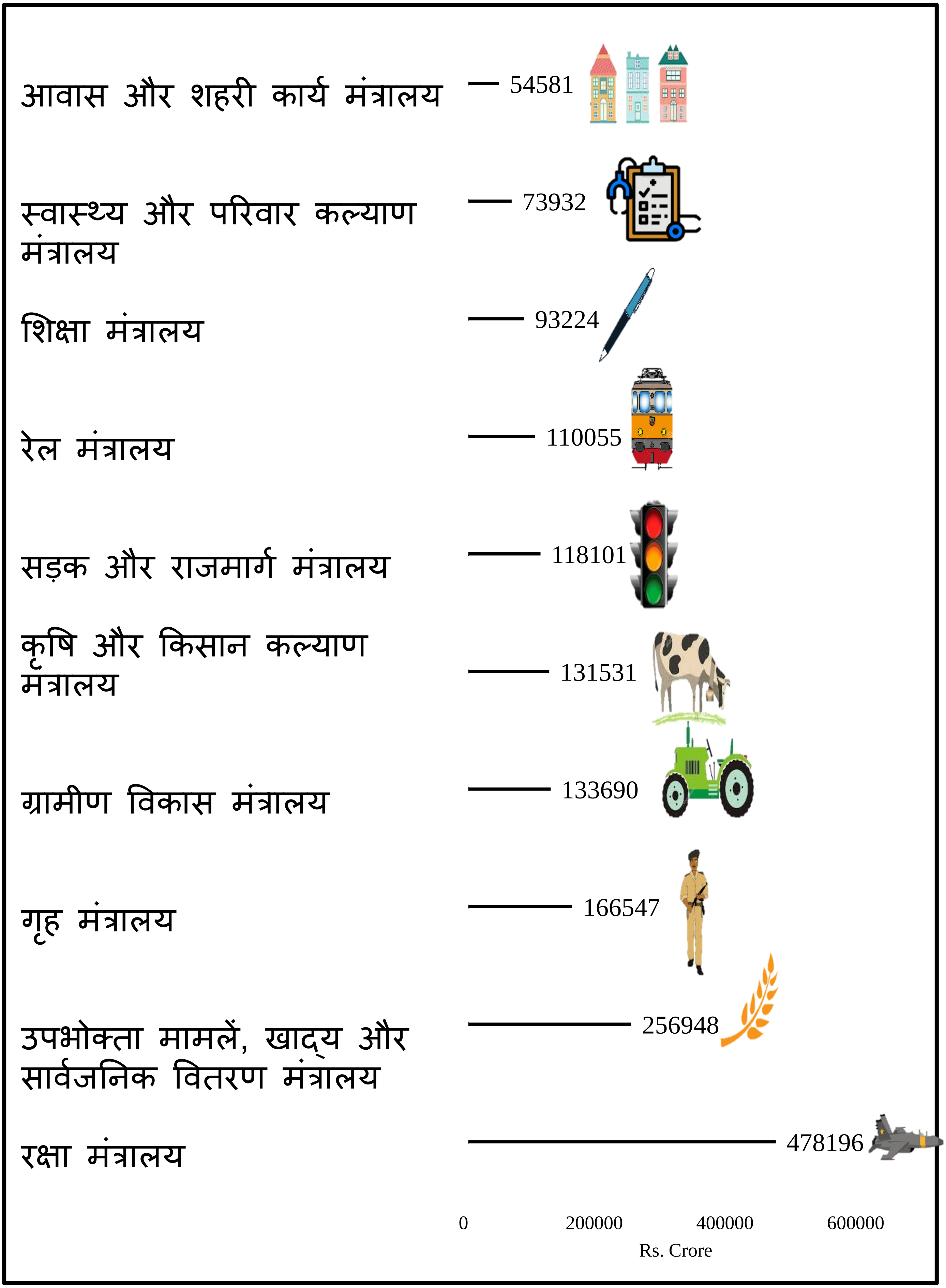

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
54581
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
73932
शिक्षा मंत्रालय
93224
रेल मंत्रालय
110055
सड़क और राजमार्ग मंत्रालय
118101
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
131531
ग्रामीण विकास मंत्रालय
133690
गृह मंत्रालय
166547
उपभोक्ता मामलें, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
256948
रक्षा मंत्रालय
478196
0
200000
400000
600000
Rs. Crore